of 34 adults and all children of the personnel attached to our Embassy in Peking were evacuated to Canton. Three adults and two children were evacuated to Hong Kong. Seventeen adults, including our Ambassador, stayed on in Peking.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

मध्य प्रदेश में प्रबन्ध में कर्मचारियों की भागीदारी योजना आरम्भ करना

1656. **श्री हुकम चन्द कछवाय :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में किन-किन कपड़ा तथा अन्य उद्योगों में प्रबन्ध में कर्मचारियों की भागीदारी योजना आरम्भ की गई है और प्रत्येक राज्य में यह भागीदारी प्रणाली कब से आरम्भ की गई है; और

(ख) किन-किन क्षेत्रों में कर्मचारियों को प्रबन्ध में भाग लेने की अनुमति दी गई है और कर्मचारियों का किस-किस प्रकार के लाभ और हानि में भी हिस्सा रहेगा ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बाल-गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख). सूचना मध्य प्रदेश सरकार से एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

'भास्कर' और 'जनबोध' के मालिकों द्वारा जमा कराई गई और उनकी और बकाया की राशि भविष्य निधि

1657. **श्री हुकम चन्द कछवाय :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्वालियर, झांसी, भोपाल, उज्जैन से प्रकाशित होने वाले दैनिक 'भास्कर' और सहडोल से प्रकाशित होने वाले 'जनबोध' के मालिकों द्वारा वर्ष 1973 से मार्च, 1976 तक, वर्षवार, भविष्य निधि की कितनी धनराशि जमा कराई गई है और कितनी धनराशि बकाया है, और

(ख) यदि हां, तो उसे ठीक समय पर जमा न कराने के लिए सरकार ने उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बाल-गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख). भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :—

"डेली भास्कर" भोपाल को उज्जैन और झांसी स्थित उसकी शाखाओं के साथ 1-3-1965 से कर्मचारी भविष्य निधि और विविध उपबन्ध अधिनियम, 1952 लागू गया था जिसमें इसकी शाखाओं को एक एक के रूप में माना गया था । मैंने अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत गैर-अनुपालन के लिए एक अभियोजन दायर किया था। तथापि प्रतिष्ठान के अधिनियम की प्रयोज्यता को चुनौती दी । इस समय भविष्य निधि प्राधिकारियों की एक अपील उच्च न्यायालय, जबलपुर के समक्ष लम्बित है । चूंकि यह मामला न्यायाधीन है, इसलिए 1973-76 के वर्षों के दौरान भविष्य निधि की बकाया राशियों को जमा करने या जमा न करने का प्रश्न नहीं उठता । 'जन-बोध' सहडोल को केवल 1-7-1976 से अधिनियम, के अन्तर्गत लाया गया है । 1973 से मार्च, 1976 के दौरान शेष राशियों/वसूलियों के ब्यौरों का प्रश्न नहीं उठता ।

मध्य प्रदेश के लिए टेलीफोन डायरेक्टरी का हिन्दी प्रकाशन निकालना

1658. **श्री हुकम चन्द कछवाय :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में टेलीफोन डायरेक्टरी का हिन्दी प्रकाशन गत कई

वर्षों से नहीं निकाला जा रहा है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है;

(ख) वर्ष 1973 से अब तक डायरेक्टरी और अनुपूरक डायरेक्टरी के अंग्रेजी तथा हिन्दी में कितने कितने अंक निकाले गये हैं और हिन्दी तथा अंग्रेजी के प्रकाशनों के बीच कितना अन्तर होता है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश एक हिन्दी भाषी राज्य है और यदि हां, तो हिन्दी डायरेक्टरी के प्रकाशन में विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या उपभोक्ताओं द्वारा डायरेक्टरी के हिन्दी अंक के बारे में अनेक शिकायतें की गई हैं और यदि हां, तो इस बारे में क्या उपचारी उपाय किए गए हैं ?

संचार मंत्री (श्री शंकर दयाल शर्मा) (क) मध्य मध्यप्रदेश सर्किल की टेलीफ़ोन डाइरेक्टरी का पिछला हिन्दी संस्करण जनवरी, 1971 में प्रकाशित हुआ था ;

(ख) 1973 से मध्य प्रदेश सर्किल के लिए अंग्रेजी की एक मुख्य डाइरेक्टरी और छह पूरक डाइरेक्टरियां प्रकाशित हुई थी । जनवरी 1971 के बाद हिन्दी की कोई भी डाइरेक्टरी या उसकी पूरक डाइरेक्टरी नहीं प्रकाशित हुई है ;

(ग) मुद्रकों और विज्ञापन एजेंटों की नियुक्ति में कुछ अपरिहार्य कठिनाइयों के कारण हिन्दी टेलीफ़ोन डाइरेक्टरी के प्रकाशन में विलंब हुआ है ;

(घ) कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है । फिर भी, मंडल स्तर पर हिन्दी डाइरेक्टरियां छपवाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं ।

राज्य स्तरों पर चिकित्सा परिषदों की स्थापना करने की योजना

1659. **श्री भागीरथ भंवर :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों ने राज्य स्तर पर चिकित्सा परिषदें स्थापित करने की योजना प्रस्तुत की है ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है ; और

(ख) केन्द्रीय स्तर पर चिकित्सा सुविधाओं पर कौन कौन सी संस्थाएं नियन्त्रण कर रही हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) जी नहीं ।

(ख) भारत सरकार का स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) तथा भारतीय चिकित्सा परिषद, चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं पर नियंत्रण रख रहे है ।

Scheduled Castes and Scheduled Tribes Employees in Shipping Corporation of India

1660. SHRI N. E. HORO: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) the total strength of employees in the Shipping Corporation of India and how many among them are from Scheduled Castes and Scheduled Tribes;

(b) whether any shortfall has been noticed in the representation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes employees in their reserved quota; and

(c) if so, the steps Government have taken to fill up these seats?